due to lack ol effective top management;

(c) whether Government propose to rotate all top posts in STC to induce efficiency; and

(d) if so, what steps are being taken to improve the management?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. R. DAS MUNSHI): (a) Steps have already been taken to appoint a full-time Chairman of State Trading Corporation as early as possible .

(b) to (d) While the performance of the State Trading Corporation is reviewed from time to time, there is no proposal with the Government to" rotaie the top management posts in the Corporation. The trade turnover of the Corporation has increased from Rs. 2551 crores in 1985-86 to Rs. 2735 crores in 1986-87. Exports have also gone up from Rs. 377 crores in 1985-86 to Rs. 642 crores in 1986-87.

Schemes of Syndicate Bank to encourage Farmers

3319. SHRI CHATURANAN MISH RA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Syndicate Bank has initiated any project/scheme to encourage farmers to grow/switch over to the cropping of special types of grapes in the Northern States on the eve of World Food Day—1987;

(b) if so, what are the broad outlines of the project/scheme as envisaged by the Syndicate Bank and the type of financial assistance that will be provided to the farmers;

(c) what are the names and addres ses of the branches of Syndicate Bank in the Northern States where the farmers will have to approach for the purpose; and

(d) what is the date on which the project/scheme was 'initialed and the number of farmers who have been benefited so far in the northern States and particularly in Haryana and Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Syndicate Bank has reported that in connection with the World Food Day, 1987 a scheme has been formulated for grape development in two development blocks of District Hissar, Haryana. Bank finance under the scheme is available for land preparation, construction of bowers, purchase of planting material and maintenance cost for the first two years. The scheme envisages developing 30 acres of grape farms with bank loan of Rs. 11.70 lakhs. The unit cost would be Rs. 30.000 per acre for the first year and Rs. 10,000 nor acre for the second year. The loans shall be repaid within a period of 10 years with initial grace period of two years. The loans shall be secured by mortgage of land and hypothecation of the crop.

(c) The address of the financing branch for the scheme is as follows:

Syndicate Bank, New Shopping Complex (Near Telephone Exchange), Hissar-125001.

(d) Syndicate Bank has reported that the scheme was launched on 16-10-87 and so far 4 beneficiaries have been sanctioned loans to the extent of Rs. 30 lakhs.

विद्युत करघा निर्यात संवधन परिषद की स्थापना

3320. श्रीमती रेणका चौधरी :
श्री रशीद मसूद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत करघा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये और इसें वर्तमान आर्थिक संकट से उभारने के लिये एक अलग विद्युतीकरण निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का सझाव सरकार के सम्मुख रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को एक पृथक विद्युत करघा निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त हुआ है। तथापि, सरकार का यह विचार है कि ऐसी निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

3321. *[Transferred to the llth December.* 1987]

आयातित खाद्य तेल की बिक्री

3322. **श्री चतुरानन मिश्र :**
श्री गुरुदास दास गुप्त :
श्री रशीद मसूद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने भारी मात्रा में आयातित खाद्य तेल को बिक्री के लिये लायसेंसधारक थोक बिक्री व्यापारियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस तेल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा एस० टी० सी० को आयातित खाद्य तेल की खुले बाजार में बिक्री के लिये निदेश दिए गए हैं ताकि देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके तथा उचित स्तर पर कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। इसका राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

झण्डेवालान दिल्ली में जेवरात निर्यात काम्पलैक्स की स्थापना

3323. **श्री रशीद मसूद** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, सरकार ने सौ प्रतिशत जेवरात निर्यात एवं कों के लिये झंडेवालान दिल्ली में एक औद्योगिक काम्पलैक्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खनिज व धातु व्यापार निगम के मार्फत सोने का आयात करने के बाद उसे इन निर्यात इकाइयों में वितरित करने का सुझाव सरकार ने मान लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एम०एम टी०सी० द्वारा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख कम्पलैक्स में स्वर्ण आभूषणों का निर्माण तथा निर्यातिक एककों के लिये स्वर्ण के स्टाक तथा बिक्री के लिये प्रस्तुत की गई योजना अब कभी भी अनमानित हो जाएगी, कार्यान्वित कर दी जाएगी।

हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े और नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

3324. **श्री रशीद मसूद** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय एन०टी०सी० मिलों द्वारा उत्पादित जनता कपड़े और नियंत्रित कपड़े को हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की सम्भावना है ?